

# हस्ताक्षरित /—

(यशपाल),

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।

हस्ताक्षरित /—  
(यशपाल),  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 7 का संशोधन।
3. धारा 13 का संशोधन।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

हि0 प्र0 विधान सभा।

1- ~~1 f{kr ule-&&~~इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन), अधिनियम, 2025 है।

2- ~~/kjk 7 dk l ákku-&&~~हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (2) के परन्तुक (क) में, "पचास" शब्द के स्थान पर "एक सौ चौतालीस" शब्द रखे जाएंगे।

3- ~~/kjk 13 dk l ákku-&&~~मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) में, "प्रत्येक स्थापन का नियोजक" शब्दों के पूर्व "दस या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

---

### ~~mís ; kvk dk .kak dFku~~

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 को दुकानों और वाणिज्यिक स्थापना में कार्य और नियोजन की शर्तों को विनियमित करने हेतु लगभग 50 वर्ष पूर्व अधिनियमित किया गया था। इसके अधिनियमित किए जाने के पश्चात् महत्वपूर्ण संस्थागत तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के दृष्टिगत अधिनियम के कतिपय उपबंधों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ताकि उसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके।

वर्तमानतः, अधिनियम की धारा 7 ओवरटाइम संकर्म को किसी तिमाही में पचास घण्टे तक सीमित करती है। ओवरटाइम मानदेय के संदाय को साधारण घण्टों की मजदूरी से दोगुना करने के अध्वधीन इस सीमा को किसी तिमाही में, प्रति तिमाही एक सौ चौतालीस घण्टों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि कर्मचारियों को और अधिक आय के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, अधिनियम वर्तमानतः समस्त स्थापनों हेतु रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य करता है। अतः इस अपेक्षा को दस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों के लिए ही सीमित किए जाने का प्रस्ताव है। इस युक्तिकरण से राज्य में व्यवसाय को और अधिक प्रोत्साहित करने की अपेक्षा है। अतः हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 में संशोधन किया जाना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

~~1/8"l3/l3 pl8ku1/2~~  
(प्रभारी मंत्री)।

धर्मशाला

तारीख....., 2025.

---

~~foUkh Kki u~~

—शून्य—

---

~~i R k kft r fo/ku l EcUkh Kki u~~

—शून्य—

---

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called as the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025.

**2. Amendment of section 7.**—In section 7 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in proviso (a) of sub-section (2), for the word “fifty”, the words “one hundred forty four” shall be substituted.

**3. Amendment of section 13.**—In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “every establishment”, the words “employing ten or more employees” shall be inserted.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 was enacted over fifty years ago to regulate the conditions of work and employment in shops and commercial establishments. In view of the significant institutional and socio-economic changes since its enactment, certain provisions of the Act require revision to enhance its relevance and effectiveness.

Section 7 of the Act, presently restricts overtime work to fifty hours in a quarter. It is proposed to enhance this limit to one hundred and forty four hours per quarter, subject to the payment of overtime remuneration at twice the normal hourly wages, so as to provide employees with greater earning opportunities. Further, while the Act currently mandates registration for all establishments, it is proposed to limit this requirement to the establishments employing ten or more persons. This rationalisation is expected to facilitate ease of doing business in the State. Hence, it has become expedient to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(HARSHWARDHAN CHAUHAN)**  
*Minister-in-Charge.*

DHARAMSHALA  
THE....., 2025

---

## FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS  
(AMENDMENT) BILL, 2025**

**A**

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments  
Act, 1969 (Act No. 10 of 1970).*

**(HARSHWARDHAN CHAUHAN)**  
*Minister-in-Charge.*

---

*Secretary (Law).*

DHARAMSHALA:  
THE....., 2025.